

Need for a Long-Term Strategy to Improve India's Healthcare System

Date	Publication
09.10.2021	Dainik Bhaskar

ड्रमैक्ट फीचर



डॉ. पी. आर. सोडानी
प्रेसीडेंट, आईआईएचएमआर यूनिवर्सिटी

डॉ. पी. आर. सोडानी, प्रेसीडेंट, आई. आई. एच. एम. आर. विश्वविद्यालय, जयपुर, 25 वर्षों से अधिक स्वास्थ्य अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं और संकाय छात्रों और शोधकर्ताओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं। प्रोफेसर सोडानी ने अकादमिक नेतृत्व, दूरदर्शिता, नीति नियोजन और रणनीतिक कार्यान्वयन का प्रदर्शन किया है। उन्होंने विश्वविद्यालय के विकास के लिए एक संगठनात्मक संस्कृति बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रोफेसर सोडानी नेतृत्व के विभिन्न स्तरों पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ शिक्षाविदों, अनुसंधान, प्रशिक्षण, और नेटवर्किंग के नेतृत्व और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं।

नीति नवाचार: सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए नीति निर्माण भारत की स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार के लिए दीर्घकालिक रणनीति की जरूरत

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में वर्णित लक्ष्यों को चार बुनियादी कार्यों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है:- 1) स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, 2) उन सेवाओं को खरीदने के लिए राजस्व जुटाना और आवंटित करना, 3) जनसंसाधनों, अस्पतालों, उपकरणों, दवाओं और आपूर्ति में निवेश करके संसाधन बनाना, और 4) नेतृत्व एवं शासकीय क्षमता। ग्रामीण क्षेत्रों में जनस्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को उप केंद्रों प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों से मिलकर एक त्रि-स्तरीय प्रणाली के रूप में विकसित किया गया है, जो कि भारत की स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली के मुख्य मूलभूत अंग का गठन करते हैं। भारत में गुणवत्तापूर्ण सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना एक चुनौती है।

भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में ग्रामीण स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उपकेंद्र कार्यरत हैं। भारत सरकार की ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट, 2019.2020 के अनुसार, 31 मार्च, 2020 तक ग्रामीण क्षेत्रों में 5,183 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 24,918 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 1,55,404 उपकेंद्र कार्य कर रहे थे। गत कई वर्षों से इन स्वास्थ्य संस्थाओं को विकसित करने के लिए सरकारों ने अपने राजस्व को उपयोग में लिया। परंतु फिर भी सामुदायिक स्तर पर इन स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं हो पाई, जो कि एक चिंता का विषय है और इसे हमें गंभीरता से लेना चाहिए। जहाँ तक उपकेंद्रों की बात है

तो 41% सरकारी भवन के बिना कार्य कर रहे हैं, 28% बिजली की उचित आपूर्ति के बिना कार्य कर रहे हैं और 15% नियमित पानी की आपूर्ति के बिना कार्य कर रहे हैं। इन उपकेंद्रों पर 14% महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता और 37% पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद रिक्त हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 24,918 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कार्यरत हैं। जिनकी हालत भी अच्छी नहीं है, क्योंकि 20% प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरकारी भवनों के बिना कार्य कर रहे हैं और 24% चिकित्सकों के पद रिक्त हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति और भी नाजुक है, जहाँ पर 31 मार्च, 2020 तक स्वीकृत पदों में से 68% सर्जन, 56%, स्त्री रोग विशेषज्ञ 67% चिकित्सक और 63% बाल रोग विशेषज्ञ के पद रिक्त थे। भारतीय जनस्वास्थ्य मानकों के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 79% सर्जन 70% प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ, 78% बाल रोग विशेषज्ञ की कमी है। भारतीय जनस्वास्थ्य मानकों के अनुसार प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक जनस्वास्थ्य विशेषज्ञ का पद भी सूचित है। कोविड-19 महामारी के इस वैश्विक अनुभव के बाद भी, सरकारों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जनस्वास्थ्य विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं कराये, जो एक चिंता का विषय है। हम सब इस समय एक कठिन दौर से गुजर रहे हैं, इसे ध्यान में रखते हुए सरकारों को बिना किसी विलम्ब के गंभीर नीतिगत निर्णय लेने चाहिए, जिससे कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कम से कम एक-एक जनस्वास्थ्य विशेषज्ञ उपलब्ध

कराया जा सके, जो कि सामुदायिक स्तर पर स्वास्थ्य प्रणाली की प्रभावशीलता को बढ़ाने में मददगार साबित होगा। इसके लिए सरकारों को उच्च शिक्षा संस्थानों से तैयार जनस्वास्थ्य विशेषज्ञों की भर्ती तुरंत करवानी चाहिए।

आईआईएचएमआर विश्वविद्यालय के बारे में

आईआईएचएमआर विश्वविद्यालय जयपुर, एक जाना-माना स्नातकोत्तर अनुसंधान विश्वविद्यालय है, जो कि पिछले कई वर्षों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रबंधकों को तैयार करने में एवं सार्व-आधारित नीति निर्माण और कार्यक्रम प्रबंधन के लिए अनुसंधान कार्य में लगा हुआ है। इसकी एक अनूठी संगठनात्मक संस्कृति है जो स्वायत्तताएँ जवाबदेही, खुलेपन और पारदर्शिता जैसे मूल्यों और लोकचर को सुनिश्चित करती है। कामकाजी पेशेवरों की क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और उद्योगों के साथ मजबूत

भागीदारी रखता है। स्नातकोत्तर शैक्षणिक कार्यक्रमों में नई शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों को अपनाने की ओर बढ़ रहे हैं। डॉ. सोडानी ने छात्र केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एनईपी की सिफारिशों को लागू करने और एकीकृत करने के लिए कार्य योजना विकसित करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। आईआईएचएमआर विश्वविद्यालय के एम.बी.ए., एम.पी.एच. एवं पी.एच.डी. कार्यक्रम बहुत ही विशिष्ट श्रेणी के हैं। ये कार्यक्रम अस्पताल प्रबंधक, स्वास्थ्य प्रबंधक, जनस्वास्थ्य प्रबंधक, फार्मास्यूटिकल प्रबंधक, विकास प्रबंधक एवं अनुसंधानकर्ता तैयार करते हैं। डॉ. सोडानी ने संस्थान स्तर पर विद्य-स्तरीय अनुसंधान विश्वविद्यालय के रूप में विश्वविद्यालय की स्थिति को समन्वित एवं मजबूत बनाया है। अपने मजबूत नेतृत्व और दूरदर्शिता के साथ उन्होंने छात्रों के लिए अभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत करके विश्वविद्यालय को अपने दृष्टिकोण और मिशन को प्राप्त करने के लिए नेतृत्व किया है।

